

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी :आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 20/2017

अपीलांत

मूलचंद पुत्र हस्तीमल जी जाति ओसवाल उम्र 61 वर्ष निवासी गढवादडा, हाल पाली पता रोटरी भवान के पास श्रीराम हास्पिटल के सामने वाली गली, पाली (राज.)

रेस्पोडेन्ट

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र महालचंद जी चिण्डालिया जाति ओसपाल निवासी चण्डालियो को चौघरा लेडिज मार्केट के पीछे, सरदार शहर जिला चुरू(राज.)
2. महेन्द्र कुमार पुत्र माणकचंद
3. प्रकाश चंद पुत्र माणकचंद
4. सुरेन्द्र कुमार पुत्र माणकचंद
5. पारस कुमार पुत्र माणकचंद
6. झंकार देवी पुत्री माणकचंद
7. इन्दु देवी पुत्री माणकचंद
8. विधा देवी पुत्री माणकचंद
9. विनिता देवी पुत्री माणकचंद
10. ललिता देवी पुत्री माणकचंद
11. नीलमदेवी पुत्री माणकचंद, रेस्पोडेन्ट संख्या 03 से 12 सभी जातिगण चिण्डालिया ओसवाल सभी निवासी चण्डालियो का चौघरा, लेडिज मार्केट के पीछे, सरदार शहर, जिला चुरू(राज)
12. मोहनराज पुत्र खीवराज जाति ओसवाल निवासी कवास तहसील बाडमेर जिला बाडमेर हाल ई 37 भगवान महावीर नगर, पाल निंक रोड, कमला नेहरू नगर अस्पताल के पास, जोधपुर(राज.)
13. रमेश कुमार पुत्र हस्तीमल जी जाति ओसवाल निवासी गढवाडा हाल भैरवा मोटर्स गीता भवन के पास, पाली।
14. केवलचंद गुलेच्छा पुत्र हस्तीमल जी गुलेच्छा निवासी पैकेज कॉलोनी पाली।
15. अनिल कुमार पुत्र केवलचंद गुलेच्छा जाति जैन, निवासी पैकेज कॉलोनी पाली।
16. शांतिलाल पुत्र हस्तीमल जाति गुलेच्छा जैन निवासी वीर दुर्गादास नगर, पाली।
17. प्रकाश चंद पुत्र मिलापचंद जी झामड निवासी गुलाबपुरा, हाल 7 शिवम अपार्टमेंट, आचार्य कृपलानी मार्ग, आर्दश नगर जयपुर (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :-

श्री मनीष राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट
रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 से 12 बावजूद सूचना अनुपस्थित
श्री जीतराम चौहान, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 14 से 16 की ओर से
श्री श्रवणसिंह चौहान विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 17 एवं 18 की ओर से
राजकीय अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट संख्या 19 की ओर से

—: निर्णय :-

दिनांक:- 18.03.2019

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पाली द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 322/2015 बअनवान राजेन्द्र कुमार व अन्य बनाम मोहनराज वगैरा में पारित आदेश दिनांक 08.06.2016 के विरुद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 11 द्वारा अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 14 से 18 के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 188, के तहत वाद प्रस्तुत किया, जो विचाराधीन है। उक्त वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी भी प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजात् का अवलोकन किए बिना ही राजस्व लोक अदालत कैम्प में जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि विरुद्ध हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अपीलांट के जवाब एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 11 की तामिल हेतु नियत थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलांट को सुनवाई का विधिवत अवसर दिये जैर अपील आदेश पारित किया है जो कि विधिसम्मत नहीं है। राजस्व लोक अदालत कैम्पों का उद्देश्य दोनो पक्षकारों की आपसी समझाईश से एवं दोनो पक्षों की आपसी सहमति अनुसार प्रकरण में निर्णय पारित किया जाना है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व कैम्प का नाजायज फायदा उठाते हुए अवैधानिक रूप से बिना पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिये बाले बाले राजस्व कैम्प में निर्णय पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश खारिज फरमावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

वकील रेस्पोजेन्ट संख्या 01 से 11 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

बहस पर मनन किया तथा दस्तावेजात् का अवलोकन किया। रेस्पोजेन्ट संख्या 01 से 11 द्वारा अपीलान्त एवं रेस्पोजेन्ट संख्या 14 से 18 के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 188, के तहत वाद प्रस्तुत किया, उक्त वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी भी प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 06.04.2016 को वादग्रस्त आराजी के संबन्ध में राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु उभयपक्ष को पाबन्द किया गया। उसके पश्चात पत्रावली दिनांक 08.06.2016 को राजस्व लोक अदालत में नियत की जाकर जैर अपील आदेश दिनांक 08.06.2016 द्वारा आदेश दिनांक 06.04.2016 को मूल वाद के अंतिम निर्णय तक कर्न्फर्म करने का आदेश प्रदान किया गया। हस्तगत प्रकरण मे दो बिन्दु उद्भूत होते है प्रथम बिन्दु यह कि क्या न्याय आपके द्वारा कैम्प कोर्ट में बिना आपसी राजीनामे के निर्णय किया जा सकता है अथवा नहीं ? इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर०सी०आर० (सिविल) 2006(4) पेज 947 सहित विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "Legal Services Authorities Act 1987, Section 20- Power of disposal of cases by Lok Adalat- No order can be passed by Lok Adalat if no compromise or settlement is or could be arrived at between parties" इसका विस्तृत विवेचन इस प्रकार किया है कि "The specific language used in sub-section of Section 20 makes it clear that the Lok adalat can dispose of a matter by way of a compromise or settlement between the parties, Two crucial terms in sun-section (3) and (5) of Section 20 are "compromise " and "setteltment" The former expression means settlement of differences by mutual concessions. it is an agreement reached by adjustment of conflicting or opposing claims by reciprocal modification of demands. As per Terms de la Ley, compromise is a mutual promise of two or more parties that are at controversy. As per Bouvier it is "an agreement between two or more persons, who to avoid a law suit, amicably settle their differences, on such terms as they can agree upon" The word "compromise " implies some element o accommodation on each side. it is not apt to describe total surrender. A compromise is always bilateral and means mutual adjustment. "Settelment" is a termination of legal proceedings by mutual consent. If no compromise or settlement is or could

राजस्व अपील प्रा. नं. 01/14
माली

be arrived at, no order and be passed by the Lok Adalat" इसी प्रकार एस0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 9194/2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए यह अभिमत प्रकट किया कि जब पक्षकारान् के मध्य राजीनामा अथवा सहमति नहीं हो, तो लोक अदालत के माध्यम से आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। उक्त न्यायिक सिद्धान्तों से यह स्पष्ट है कि राजस्व लोक अदालत के माध्यम से निर्णय पारित करने हेतु दोनों पक्षों की उपस्थिति एवं उनमें राजीनामा होना आवश्यक है, बिना राजीनामे के लोक अदालत के तहत आदेश पारित किया जाना विधिसम्मत नहीं है। उक्त अभिनिर्णयों से हस्तगत प्रकरण पूर्णतया प्रभावित होता है। द्वितीय बिन्दु यह है कि क्या रेकर्डेड खातेदार को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाना न्यायोचित है अथवा नहीं? इस सम्बन्ध **2013(2) RRT Page 828 Rameshi vs. Kajod & ors** में प्रतिपादित किया कि "Rajasthan tenancy act, 1955-Sec. 212- temporary Injunction application rejected & affirmed by the appellate Court-Land not recorded in the Khatedari of the plaintiff- No. T.I. can be granted against the recorded khatedar- Possession of non-petitioners no. 3 & 4 would be treated after the death of 'B'- Petitioner failed to prove possession- objection raised can only be decided during trail-Concurrent judgments- Held, No illegality or perversity in the order. **2012(2) RRT Pg. No. 1439 Pooran Chand & ors. V/s. Gopal Prasad & ors.** में प्रतिपादित किया कि " Rajasthan tenancy act, 1955-Sec. 212- Trail court restrained both the parties but RAA Dismissed the application of the petitioners - Land recorded on Khatedari of GP - No Revenue entry in favour of the petitioners - Khatedari of 'GP' is based in the registered sale deed Appellate court not found the Prima facie case in favour of the petitioner 'KP' & ors. - Concurrent finding regarding Khatedari & possession - No T.I. can be granted against the recorded Khatedar holding possession - Held, R.A.A. has not committed any illegality or jurisdictional error.(Para's 7,8). **2009(2) RRT Pg. No. 1327 Nannu Ram (Dead) through L.Rs. V/s.Jorlam & ors.** में प्रतिपादित किया कि "Rajasthan tenancy act, 1955-Sec. 212- Temporary Injunction RAA st aside the order - Revision - suit for declaration on the basis of adverse possession - Petitioner admitted that non-petitioners are recorded Khatedar- Both the parties are claiming possession & their question cannot be decided as this

stage - Held, no error in the order & upheld. (Para's 5,7). **RRT 2013(1) Pg. No. 133 Kalu & ors. V/s. Jagdish Prasad & ors.** में प्रतिपादित किया कि "Rajasthan tenancy act, 1955-Sec. 212- RAA set aside the order of granting TI - Non-petitioner purchase the land from the recorded Khatedar of the land by regd. Sale deed- Petitioners are required to prove their case by producing evidence - Prima facie case in favour of the non- petitioners - Held, No Jurisdictional error in the order. (Para's 7,8). **RRT 2013(2) Pg. No. 805 Narayan Singh & ors. V/s. Ramesh** में प्रतिपादित किया कि " Rajasthan tenancy act, 1955-Sec. 212- Temporary injunction - Trail court directed the parties to maintain the status quo of revenue record & at site - Appeal dismissed - Order should have been passed on merits considering the three necessary elements- Held, orders are set aside & case remanded to trail Court.(Para's 7 ,9). **2006-07(supp.) RRT, Pg. No. 368 Dhanni V/s. Ramuram** में प्रतिपादित किया कि "Rajasthan tenancy act, 1955-Sec. 212- Revision - Scope - Temporary injunction refused- Order upheld in appeal - Petitioner failed to prove prima facie case, balance of convenience & irreparable loss - Rights & title will be decided in regular suit - Possession not proved - Scope of revision is very limited - Re-appreciation of facts in not. Justified-Held, Revision deserves to be dismissed.(Para's 9,10). **RRT 2015(1) Pg. No. 633 Awtar Khan V/s. Mehar Bano & ors.** में प्रतिपादित किया कि "Rajasthan tenancy act, 1955-Sec. 212- Temporary Injunction - Applications dismissed - Respondent No. 1 & 2 are the recorded Khatedar of the land & no temporary Injunction can be granted - Concurrent finding - Limited scope - Held, No material illegality or jurisdictional error in the order. (Para's 8,9). **RRT 2015(1) Pg. No. 560 Jhanwari Lal & ors V/s. the Board of Revenue - ors.** में प्रतिपादित किया कि " Rajasthan tenancy act, 1955-Sec. 212- Temporary Injunction - R.A.A. Set aside the order of granting T.I. & Affirmed by the BOR - Registered sale deed in favour of 'B' husband of the respondent no. 2 - No prima facie case found in favour of the petitioners -

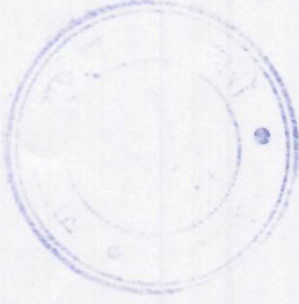
Held, No error in order of rejecting revision. (Para's 9,10,11). **RRT 2014(2) Pg. No. 1301 Goparam & ors V/s. Harima Ram & ors.** में प्रतिपादित किया कि " Rajasthan tenancy act, 1955-Sec. 212- Temporary Injunction - Application for granting T.I. was dismissed - Defendants / non-applicants are the recorded Khatedar of the land & they are in possession of the land - Concurrent findings - Held, No T.I. can be granted & order suffered with no irregularity or illegality.(Para 7). **RRT 2004(1) Pg. No. 587 Kaushlya V/s.Chotu & ors.** में प्रतिपादित किया कि " Rajasthan tenancy act, 1955-Sec. 212- P&N purchased the land from non-petitioner nos. 1 to 3 who subsequently sold to non-petitioners nos. 5 to 9 & they are in possession of land - No Possession of plaintiff - 1/5 share claimed by plaintiff in property being ancestral - No prima facie, or balance of convenience in favour of petitioners - Held, no illegality or irregularity in the order of R.A.A. (Para's 7,8). **RRT 2009 (2) Pg. No. 1398 Ramjuddin & ors V/s. Ganesh Kumar & ors.** में प्रतिपादित किया कि " Rajasthan tenancy act, 1955-Sec. 212- Temporary Injunction - Name of non-petitioner no. 1 entered wrongly in the revenue record - Suit relating to land is pending disposal since 1995 - Non Petitioner sold the Land to non-petitioner no. 2 & 3 pending suit- Non-petitioner no. 1 recorded Khatedar & petitioner has not produced any document of possession - No T.I. can be granted against a recorded Khatedar - Concurrent findings - Interference not justified.(Para 7). **RRT 2009(2) Pg. No. 1393 Dhupa V/s. Mamman & ors** में प्रतिपादित किया कि " Rajasthan tenancy act, 1955-Sec. 212 & 230 - Application for granting T.I. rejected in absence of the prima facie case - revision - Non-Petitioners are recorded Khatedar of the disputed land & they are in possession - No proof produced to show possession - Concurrent finding - Held, No case made out for interference.(Para's 8,9). **RRT 2001(2) Pg. No. 1261 Smt. Prakash Kanwar & ors V/s. Kailash Chandra & ors.** में प्रतिपादित किया कि " Rajasthan tenancy act, 1955-Sec. 212- Land

in disputed is a firm property -) share was of plaintiff's father & half share was of 'S' & 'R' who sold it to 'R', 'K' & 'R' through regd. Sale deed - 'R', 'K' & 'R' again sold to land to 'P', 'A' & 'M' through Regd. Sale deed - Parties are joint recorded Khatedar & co-tenant - Held, No order of T.I. can be passed against co-tenant to deprive them from use if their share & also cannot be evicted & orders are set aside.(Para's 9, 10). **RRT 2010(2) Pg. No. 1392 Ramkaran & ors. V/s. Smt. Ghewari & ors.** में प्रतिपादित किया कि " Rajasthan tenancy act, 1955-Sec. 212-Temporary Injunction - Application and Appeal rejected - G.R. was the co-tenant & he sold the land to 'G' & and she became Khatedar - No name of 'KR' in Kh. No. 10 nor he has possession - No document produced to prove the land ancestral - Recorded Khatedar Cannot be restrained from selling his share - Concurrent finding - Held, No illegality in the order. (Para's 11, 12). **RRT 2009(2) Pg. No. 1327 Nannu Ram (dead) through L.Rs. V/s. Jormal & ors.** में प्रतिपादित किया कि " Rajasthan tenancy act, 1955-Sec. 212- Temporary Injunction - R.A.A. set aside the order - Revision - Suit for declaration on the basis of adverse possession - Petitioners admitted that non-petitioners are recorded Khatedar - Both the parties are claiming possession & their question cannot be decided at this stage - Held, No error in the order & upheld. (Para's 5,7).
 वादग्रस्त आराजी अपीलांट एवं रेस्पोजेन्ट की सहखातेदार खरीदशुदा आराजी है। जिसके संबध में बंटवाडे से संबधित दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। एवं प्रकरण मे निर्विवाद सत्य है कि अपीलांट एवं रेस्पोजेन्ट वादग्रस्त के रेकर्डेड खातेदार है एवं कानूनन जिन्हे अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये पाबन्द किया जाना न्यायोचित नहीं है। साथ ही जैर अपील आदेश राजस्व लोक अदालत कैम्प में पारित किया गया है। जो आपसी राजीनामे व सहमति के बिना पारित किया गया है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश हाजा न्यायालय की राय में समर्थन योग्य नहीं है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पाली द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 322/2015 बअनवान राजेन्द्र कुमार व अन्य बनाम मोहनराज वगैरा में पारित आदेश दिनांक 08.06.2016 अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

निर्णय आज दिनांक 18.03.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली